Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 4, July-2021, ISSN 2230-7540

बीड़ी कारखानों में कामकाजी महिला की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर एक अध्ययन

Chandraprabha Baijnath Nagde[1]*, Dr. Umesh Kumar Yadav[2]

[1] Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

[2] Professor, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

सार - ***बीड़ी श्रमिक अक्सर समाज में सबसे कमजोर समूह होते हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण भारत में बीड़ी रोलिंग पर निर्भर होते हैं। कम मजदूरी और ठेकेदारों का लगातार शोषण, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की कमी और सरकारी नीतियों की उपेक्षा के बावजूद वे जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत में कई बीड़ी कार्यकर्ता महिलाओं और उनके कार्यबल से अलग हैं जो अपने घरों से काम करते हैं, और इस कारण से उन्हें व्यापक आर्थिक शोषण के लिए आसानी से लक्षित किया जाता है। एमईयू श्रमिकों को कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं।***

कीवर्ड - ***बीड़ी कारखान, कामकाजी महिला, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति***

----------X----------

परिचय

बीड़ी सुगंधित तम्बाकू साइट्रेट से बनी सिगरेट है। तंबाकू की कम खपत के साथ, भारत और उसके पड़ोसी देश भी कम आर्थिक समूहों और ग्रामीण आबादी में बहुत लोकप्रिय हैं। भारत में हर साल लगभग 800 मिलियन बोलियां बेची जाती हैं, जो 8 से 1 के अनुपात में है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक हैं क्योंकि यह अधिक निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और डामर प्रदान करती है। बीड़ी उद्योग ग्रामीण भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग और आजीविका का एक सहायक स्रोत प्रदान करता है। यह उद्योग भारत में महिला बीड़ी श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्योग देश के असंगठित क्षेत्रों में सबसे बड़ा है, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने एक बहुत बड़ी सेना का इस्तेमाल किया है। बीड़ी उद्योग ने हजारों लोगों को रोजगार दिया है, और उनका स्वास्थ्य हानिकारक है।

भारत में तंबाकू

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में, भारत में बीड़ी उद्योग बढ़ने लगा। सबसे पुरानी बीड़ी निर्माण फर्म की स्थापना 1887 के आसपास हुई थी और 1930 तक बीड़ी उद्योग पूरे देश में फैल गया था। सिगरेट से कीमत के अंतर ने मजदूर वर्गों द्वारा बीड़ी के उपयोग का पक्ष लिया और इस घरेलू उत्पाद ने जल्द ही सिगरेट को तंबाकू की खपत के प्रमुख रूप के रूप में पूरक बनाया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा अपनाई गई कर नीतियों ने भी सिगरेट की तुलना में बीड़ी के उपयोग का समर्थन किया। इसने बीड़ी की खपत में वृद्धि को बढ़ावा दिया (भारतीय केंद्रीय तंबाकू समिति, 1960; तंबाकू विकास निदेशालय, 1997; कोरी, 1998; तंबाकू बोर्ड, 2002)।

तंबाकू का अर्थशास्त्र, जिसने इसे भारत में पेश किया और औपनिवेशिक शासन के दौरान इसे मजबूत किया, ने भी स्वतंत्र भारत में भी तंबाकू व्यापार को संरक्षण की स्थिति के लिए एक अनिवार्य कारण प्रदान किया। तैयार राजस्व जो वार्षिक बजट को मजबूत करता है, एक तंबाकू भूखे विश्व बाजार में निर्यात करने की क्षमता और लाखों लोगों को रोजगार के अवसरों की पेशकश ने तंबाकू को एक फसल और एक उद्योग के रूप में प्रोत्साहित करने का औचित्य प्रदान किया (संघवी, 1992)।

यद्यपि अर्थशास्त्र भारत में तम्बाकू के प्रतीत होने वाले कठोर विकास को बढ़ावा देने वाला प्रमुख बल हो सकता है, ऐसे कई सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी हैं जिन्हें पहचानने की आवश्यकता है, ताकि सामाजिक, धार्मिक और जातीय उपसमूहों में इसके उपयोग में भिन्नता हो

www.ignited.in

सके। समझा। तंबाकू के भारत में प्रवेश करने के समय से ही ऐसे कारक संचालित हुए हैं, हालांकि सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारकों की प्रकृति जो तंबाकू के प्रति व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है, समय, क्षेत्र, धार्मिक संप्रदाय और सामाजिक वर्ग के साथ भिन्न हो सकती है।

कृषि, औद्योगिक और निर्यात क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के कारण तम्बाकू भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान रखता है। भारत विश्व में तम्बाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तंबाकू की खेती के मामले में चीन और अमेरिका क्रमश: पहले और तीसरे स्थान पर हैं। ब्राजील, तुर्की, जिम्बाब्वे, मलावी, इटली और ग्रीस अन्य प्रमुख तंबाकू उत्पादक देश हैं। तम्बाकू इन देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2000- 2001 में, भारतीय अर्थव्यवस्था में तंबाकू का योगदान कितना विस्तार होना था?

₹81,820 मिलियन, जो कुल उत्पाद शुल्क संग्रह का लगभग 12 प्रतिशत था। इसी अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन ₹9,030 मिलियन था, जो भारत के कुल कृषि निर्यात का 4 प्रतिशत था (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इओनॉमी, 2004)।

आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु भारत के प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य हैं। भारत का लगभग 65 प्रतिशत उत्पादन आंध्र प्रदेश (34 प्रतिशत), गुजरात (22%) और कर्नाटक (11%) से होता है। तम्बाकू उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी उगाया जाता है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का देश के कुल तंबाकू उत्पादन में 90 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। वर्तमान में, भारतीय तंबाकू सभी महाद्वीपों में फैले 80 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है।

भारत में एक बड़ा, अत्यधिक एकीकृत तंबाकू उद्योग है, जिसमें तंबाकू की कई किस्मों की खेती, विभिन्न तंबाकू उत्पादों का निर्माण, जिसमें असंसाधित और चबाने वाले तंबाकू शामिल हैं, और एक व्यापक वितरण और खुदरा प्रणाली शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में, मजबूत कीमतों, घरेलू खपत, और तंबाकू के लिए अच्छी निर्यात मांग और अन्य फसलों की कम कीमतों के संयोजन ने तंबाकू के विकास को नकदी फसल से व्यावसायिक विचारों से जुड़े एक विनिर्माण उद्योग में मदद की। भारत में तंबाकू उद्योग में (i) पत्ती तंबाकू, (ii) धूम्रपान उत्पाद जैसे सिगरेट और बीड़ी और (iii) विभिन्न चबाने वाले तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, वितरण और खपत शामिल है। बहुराष्ट्रीय निगमों के वर्चस्व वाले उद्योग का संगठित क्षेत्र इस क्षेत्र के लिए समर्थन देने में सबसे आगे है। असंगठित क्षेत्र भी गरीबों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के सामूहिक नियोक्ता के रूप में अपनी भावनात्मक अपील का फायदा उठाता है।

तंबाकू की खेती, निर्माण और विपणन से प्राप्त होने वाले तात्कालिक और ठोस लाभ किसानों को तंबाकू उगाने के लिए और सरकार के लिए तंबाकू की खेती और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करते हैं। तम्बाकू एक ऐसी वस्तु से विकसित हुआ है जिसे बहुत महत्व और मूल्य दिया गया था और इसलिए सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी के दौरान वस्तु विनिमय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, बाद की अवधि में नकदी फसल के लिए।

भारतीय तंबाकू उद्योग में रोजगार की संरचना मोटे तौर पर भारत में तंबाकू उत्पादों के लिए उपभोक्ता बाजार की संरचना को दर्शाती है। विशेष रूप से, बीड़ी के उत्पादन का प्रभाव घरेलू उद्योग के विनिर्माण क्षेत्र के भीतर रोजगार के अवसरों पर हावी है क्योंकि यह एक अत्यधिक श्रम गहन गतिविधि है और इसमें सिगरेट निर्माताओं द्वारा नियोजित की तुलना में बहुत कम परिष्कृत विनिर्माण तकनीक शामिल है।

बीड़ी रोलर्स की स्वास्थ्य समस्याएं

तंबाकू की कटाई में काम करने वालों में निकोटीन विषाक्तता के लक्षण होते हैं। बीड़ी बनाने का काम ज्यादातर घरों में होता है। घर में रखने से खाना जल्दी खराब हो जाता है और तंबाकू की गंध से परिवार के सदस्यों को जी मिचलाने और सिर दर्द होने लगता है। वे लगातार तंबाकू की धूल के संपर्क में रहते हैं और लंबे समय तक बैठे रहते हैं, ये श्रमिक आमतौर पर सांस की जलन, पीठ और गर्दन में दर्द, गठिया और स्त्री रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करते हैं। बीड़ी रोलर्स में सिरदर्द, जी मिचलाना, चक्कर आना, आंखों में जलन और लैक्रिमेशन का भी अनुभव होता है। बीड़ी श्रमिकों में क्षय रोग, दमा प्रमुख रोग और मृत्यु के कारण हैं।

महिला बीड़ी रोलर्स भी लिंग और जाति के अंतर के आधार पर मौखिक और शारीरिक शोषण की रिपोर्ट करती हैं। उंगलियों पर मोटी त्वचा के कारण अधिकांश बीड़ी रोलर्स 45 वर्ष की आयु से अधिक काम नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया

www.ignited.in

जाता है (गुप्ता और अस्मा, 2008)। तंबाकू के खेतों में काम करने वाले उन बीड़ी श्रमिकों के सामने कई व्यावसायिक खतरे भी हैं, जिनमें स्वास्थ्य संबंधी खतरे जैसे कि हरी तंबाकू की बीमारी, कीटनाशक का जोखिम और निकोटीन विषाक्तता शामिल हैं और जबकि तंबाकू की खेती बाल श्रम के उपयोग में अद्वितीय नहीं है, विशेष रूप से इसके द्वारा उत्पन्न खतरे तंबाकू की खेती से इन बच्चों को चोट और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है (एफ्रोयमसन, 2002)।

बीड़ी के उत्पादन (सस्ते तंबाकू से बनी छोटी, सस्ती, हाथ से लुढ़की सिगरेट और टेंड लीफ में रोल्ड, आमतौर पर भारत में धूम्रपान किया जाता है) में गहन श्रम शामिल है; तंबाकू उगाना, तोड़ना, तेंदूपत्ता इकट्ठा करना और बीडियों को रोल और पैकेजिंग करना। हालांकि कोई सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान (सीटीआरआई) ने अनुमान लगाया है कि भारत में 15 राज्यों में फैले तंबाकू की खेती में 60 लाख से अधिक किसान और 20 मिलियन खेतिहर मजदूर लगे हुए हैं। बीड़ी रोलिंग तंबाकू के थोक और खुदरा बिक्री में लगे अनुमानित 4.4 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करती है (गुप्ता, 2008)।

भारत में बीड़ी उद्योग

भारत में बीड़ी उद्योग श्रम प्रधान है। चूंकि बीड़ी रोलिंग को मोटे तौर पर एक कुटीर उद्योग माना जाता है, यह विनिर्माण स्तर पर बहुत अधिक रोजगार पैदा करता है। उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण (1997- 1998) के आंकड़ों से यह अनुमान लगाया गया है कि तंबाकू निर्माण उद्योगों के लगभग 85 प्रतिशत कर्मचारी बीड़ी उद्योग में कार्यरत हैं।

भारत में तंबाकू उद्योग केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कई करों के अधीन है। केंद्र सरकार सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री से मुख्य रूप से एक्स-फ़ैक्टरी आधार पर गणना किए गए उत्पाद शुल्क के माध्यम से राजस्व जुटाती है। भारतीय तंबाकू उद्योग के एक हालिया अध्ययन में बताया गया है कि पारंपरिक तंबाकू उत्पाद, जैसे कि बीड़ी, चबाने वाला तंबाकू और धुआं रहित तंबाकू, राष्ट्रीय उपभोक्ता बाजार का 81 प्रतिशत हिस्सा है और फिर भी वे तंबाकू उत्पादों से एकत्रित कुल तंबाकू उत्पाद शुल्क का केवल 12 प्रतिशत शामिल हैं। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, 2002)।

बीड़ी धूम्रपान का संबंध निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा से होता है, और नियमित सिगरेट की तुलना में तम्बाकू से भरे ये पत्ते सस्ते होते हैं। उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोग जो धूम्रपान बीड़ी करते हैं, वे अक्सर लोगों की नज़रों में ऐसा करते हैं।

बीड़ी के ब्रांड प्रतिष्ठान

बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 और उत्पाद शुल्क कानूनों के तहत व्यापार चिह्न और अपेक्षित लाइसेंस के साथ उद्योग के लोकप्रिय प्रतिष्ठान हैं। ये प्रतिष्ठान देश के विभिन्न हिस्सों से कच्चे माल की खरीद करते हैं, उन्हें संसाधित करते हैं और उन्हें अपनी शाखाओं या ठेकेदारों को बीड़ी रोल करवाने के लिए वितरित करते हैं। अन्य कार्य जैसे छँटाई, जाँच, बेकिंग, लेबलिंग, पैकिंग और मार्केटिंग आदि, इन प्रतिष्ठानों में या उनकी बड़ी शाखाओं में नियोक्ताओं द्वारा किए जाते हैं। बड़े व्यापार चिह्न प्रतिष्ठानों की बड़ी संख्या में छोटी और बड़ी शाखाएँ हैं जो राज्य के बाहर भी फैली हुई हैं। अधिकांश प्रतिष्ठानों में बीड़ी रोलिंग का काम ठेकेदारों को सौंपा जाता है। हालांकि, कुछ बड़े प्रतिष्ठानों के मामले में सहायक प्रतिष्ठानों को बीड़ी रोलिंग भी ठेकेदारों के माध्यम से बीड़ी रोल कराने के लिए शाखाओं के अपने नेटवर्क के साथ सौंपा गया है।

ठेकेदारों से सीधे लेन-देन के लिए विभिन्न स्थानों पर बीड़ी प्रतिष्ठानों के अपने डिपो हैं। चूंकि बीड़ी बनाना अत्यधिक श्रमसाध्य गतिविधि है, जिसमें घरेलू कामगारों का वर्चस्व होता है, इसलिए उनके माध्यम से बीड़ी को घुमाने का कार्य ठेकेदारों को सौंपा जाता है। ट्रेडमार्क प्रतिष्ठानों की शाखाओं और डिपो द्वारा ठेकेदारों को लगाया जाता है। वे कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं और हरी बीड़ी एकत्र करते हैं और उन्हें मुख्य औद्योगिक परिसर में ले जाते हैं जहां इन्हें बेक किया जाता है, लेबल किया जाता है, पैक किया जाता है और विपणन किया जाता है। हालांकि, कुछ मामलों में, बड़े व्यापार चिह्न प्रतिष्ठानों की शाखाएं कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं, हरी बीड़ी एकत्र करती हैं और उन्हें सीधे उस ट्रेड मार्क प्रतिष्ठान की ओर से बेक, लेबल, पैक और विपणन करती हैं। इन गतिविधियों को करने के लिए, वे प्रबंधकों, लेखाकारों, क्लर्कों, फर्नेसमैन, सॉर्टर्स, चेकर्स, पैकर्स आदि को नियुक्त करते हैं।

गैर-ब्रांडेड बीड़ी प्रतिष्ठान

www.ignited.in

गैर-ब्रांडेड प्रतिष्ठान आमतौर पर आकार में छोटे होते थे और अक्सर अपेक्षित लाइसेंस के बिना संचालित होते थे। फिर भी वे बीड़ी के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है कि उन्हें प्रति वर्ष 20 लाख से कम बीड़ी का उत्पादन करने वाले छोटे बीड़ी निर्माताओं को संरक्षण के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। वस्तुत: आबकारी छूट की आड़ में एक समानांतर उद्योग चल रहा था और राज्य के भीतर और बाहर अधिकांश प्रतिष्ठानों का गैर-ब्रांडेड हरी बीड़ी का फलता-फूलता व्यवसाय है। ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालन के आकार ने उत्पाद शुल्क छूट की आड़ में बीड़ी के गुप्त उत्पादन के बारे में एक स्पष्ट विचार दिया। ट्रेड मार्क प्रतिष्ठानों ने महसूस किया कि इस तरह के बीड़ी प्रतिष्ठानों ने कानून का पालन करने वाले बीड़ी प्रतिष्ठानों और पूरे उद्योग के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। बीड़ी जैसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग में, एक स्पष्ट उत्पाद छूट ने लाभप्रदता, व्यवहार्यता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया। इन प्रतिष्ठानों। जाहिरा तौर पर, एक व्यापार चिह्न या ब्रांड प्रतिष्ठान के लिए काम करने वाले ठेकेदारों ने बीड़ी रोलर्स को व्यापार चिह्न प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक बीड़ी रोलिंग के काम के लिए लगाया था, लेकिन वास्तविक व्यवहार में उन्होंने बीड़ी रोलर्स के एक बड़े दल को लगाया और बीड़ी का एक बड़ा हिस्सा रोल किया। गुप्त तरीके से। हालांकि, राज्य में बीड़ी रोलर्स की सही संख्या का पता लगाना संभव नहीं था, जिसमें देश में बीड़ी उत्पादक राज्यों में बीड़ी रोलर्स का उच्चतम अनुपात (17%) है।

कार्य की प्रकृति

इस समूह में बीड़ी रोलर्स के अलावा अन्य कर्मचारी शामिल हैं। बीड़ी रोलर्स से हरी बीड़ी एकत्र करने के बाद, अन्य संबंधित गतिविधियाँ बीड़ी श्रमिकों द्वारा विभिन्न चरणों में की जाती हैं। वे निर्माताओं द्वारा सीधे अपने प्रतिष्ठानों के परिसर के भीतर नियोजित होते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की इस श्रेणी का अनुपात गतिविधि की मात्रा पर निर्भर करता है।

बीड़ी कामगारों का वर्गीकरण

ये श्रमिक विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत आते हैं और समय के साथ भविष्य निधि, बोनस, ग्रेच्युटी आदि लाभों के हकदार होते हैं।

1. उत्पादन

रोज़गार के आकार को ध्यान में रखते हुए दैनिक उत्पादन का आकलन बहुत आसानी से किया जा सकता है। आम तौर पर प्रतिदिन एक लाख बीड़ी बनाने के लिए 100 बीड़ी रोलर्स की आवश्यकता होती है। उत्पादन जितना बड़ा होगा, प्रतिष्ठान का आकार उतना ही अधिक होगा। अध्ययन के लिए तैयार की गई अनुसूचियों के माध्यम से उत्पादन डेटा को नियोक्ताओं और बीड़ी रोलर्स से अलग से एकत्र किया गया था। नियोक्ता को उत्पाद शुल्क के आकलन के लिए निर्धारित प्रपत्र में अपने उत्पादन का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में उपस्थिति, पीस रेटेड श्रमिकों के उत्पादन, मजदूरी, कटौती आदि से संबंधित अभिलेखों के रखरखाव का भी प्रावधान है। ऐसे मामलों में जहां ये रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे, नियोक्ताओं के मौखिक संस्करणों के माध्यम से आवश्यक जानकारी एकत्र की गई थी। इस जानकारी की स्पष्ट सीमाएँ थीं क्योंकि कुछ नियोक्ता, छोटी इकाइयों को चलाने के लिए न केवल रोजगार के आकार को छुपाने की प्रवृत्ति रखते थे बल्कि कानून के तहत कानूनी प्रावधानों से बचने के लिए उत्पादन की मात्रा को भी छुपाते थे। बीड़ी रोलर्स द्वारा रोल की गई बीड़ी की संख्या आमतौर पर नियोक्ताओं द्वारा उन्हें प्रदान की गई लॉग बुक में उपलब्ध होती थी। हालांकि, इसके अभाव में बीड़ी रोलर्स द्वारा दी गई जानकारी पर भरोसा करना पड़ा। इस जानकारी ने उत्पादन में बीड़ी रोलर्स के आश्रितों के हिस्से को हमेशा छुपाया।

2. आश्रितों का योगदान

तेंदूपत्ता और तंबाकू बीड़ी के मुख्य घटक हैं। तंबाकू भरने के लिए बीड़ी को काटने/बनाने से पहले तेंदूपत्ता को 6-8 घंटे तक कूटना आवश्यक है। यह सारी प्रक्रिया बीड़ी रोलर्स द्वारा स्वयं या परिवार के सदस्यों की सहायता से उनके आवास पर की जाती है। इसलिए, रोलिंग बीड़ी में परिवार के सदस्यों के योगदान का आकलन करने के लिए, मदद करने वाले आश्रितों के उत्पादन को पंजीकृत गृह श्रमिकों से अलग करना आवश्यक है।

असंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाएं

मजदूरी के अभाव में रोज़गार पाने वाली महिलाएँ हाल के दिनों में घरेलू उद्योगों जैसे बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, अचारबनाने, मसाला, पापड़, मसाले अगरपथी, माचिस की तिल्ली इत्यादि के रूप में स्वरोजगार की माँग कर रही हैं।

www.ignited.in

फ्रीलांस जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, फाइनआर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट और कुछ अपरंपरागत क्षेत्र जैसे हेयर ड्रेसर, ब्यूटीशियन, मास्स्यूज़, टूरिस्ट गाइड आदि नौकरियों में भी खुद को व्यस्त रखा। ये जॉब बड़े शहरों और महानगरों में लोकप्रिय हो रहे हैं।

असंगठित में नियोजित मजदूरी ज्यादातर कुशल, अर्ध-कुशल, अकुशल और आकस्मिक कामगार और निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों में अनुबंधित श्रमिक, अंशकालिक और पूर्णकालिक घरेलू नौकर, विभिन्न मध्य वर्गीय परिवारों में काम करने वाले बाल अटेंडेंट के लिए होती है। माता-पिता द्वारा दिखाए गए भेदभाव के कारण शिक्षा और कौशल स्तर उनके लिए बहुत कम है। ग्रामीण भारत में, श्रमिकों का सबसे बड़ा वर्गकृषि में लगा हुआ है। वे असंगठित, शोषित और उत्पीड़ित हैं।

यह एक तथ्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में सक्षम महिलाओं में से कम से कम आधी वास्तव में कामकाजी महिलाएं हैं। वे खेतों में काम करते हैं। वे मवेशियों का प्रबंधन करते हैं। वे घर के लिए और कभी-कभी खेत के लिए भी पानी लाते हैं। वे भूसीमशीनों पर काम करते हैं। यदि वे इन सभी कार्यों से वापस ले लिए जाते हैं तो पुरुष सदस्यों की आय घटकर आधी हो जाएगी जो वे कमाते हैं। लेकिन इन महिलाओं को एक गरीब कामकाजी महिला का दर्जा दिए बिना एक दिन में सोलह घंटे से अधिक काम करने के लिए केवल गृहिणी माना जाता है।

अज्ञानता, परंपरा बाध्य दृष्टिकोण, अशिक्षा, कौशलकीकमी, रोजगार की मौसमी प्रकृति, विभिन्न प्रकार के भारी शारी रिककार्य, सीमित भुगतान के साथ काम के लंबे घंटे, पुरुषों और महिलाओं के वेतनसंर चनाओं में भेदभाव, नौकरी की सुरक्षा की कमी, व्यापक कानून की कमी हैं, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को कवर करने के लिए, रोजगार में प्रतिस्पर्धा और परिणामी चित्रण। न्यूनतम मजदूरी, काम की जगह पर न्यूनतम सुविधाओं कीक मी, बीमार इलाज, बंधन और अलगाव आदि असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के रोजगार की कुछ विशेषताएं हैं।

संगठन के क्षेत्र में कामकाजी महिलाएं

विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार विनिमय द्वारा आरक्षित कुछ रिक्तियां हैं, ज्यादातरशिक्षण, नर्सिंग, दाई, रिसेप्शन आदि जैसे पारंपरिक व्यवसायों में महिलाएं अन्य प्रकार की सामान्य रिक्तियों जैसे कि आशुलिपिक, टाइपिस्ट, क्लर्क, लाइब्रेरियन, टेलीफोन ऑपरेटर, चिकित्सक, वकील, प्रशासक और अधिकारी के लिए हकदार हैं। उन्हें पुलिस बल सहित सभी भारतीय सेवाओं में भर्ती किया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है, वेहर जगह लहरें बना रहे हैं और कोई भी महत्वाकांक्षी महिला और इच्छुक महिला के लिए बंद नहीं है।

कामकाजी महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक कारक

ऐसे कई कारक हैं जो सामाजिक आर्थिक भाग्य तक पहुँचने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने से महिलाओं कोबाधित करते हैं। यहां चर्चा किए गए कुछकार कों में शामिल हैं: सांस्कृतिक कारक, शैक्षिक कारक और वित्तीय कारक।

निष्कर्ष

बीड़ी उद्योग में उत्पादन संबंध और प्रासंगिक कारक बदल गए हैं और अधिक जटिल हो गए हैं, लेकिन श्रमिक श्रमिकों को बनाए रखने और नियोक्ताओं के साथ व्यवहार करने के लिए पारंपरिक रणनीतियों का उपयोग करना जारी रखते हैं। 90 प्रतिशत से अधिक सदस्यों का संघ में नेता के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं है या वे संघ के निर्णय की प्रक्रियाओं में भाग ले रहे हैं। समुदाय महिलाओं के अकाल के बारे में जागरूकता प्रदान करके श्रमिक परिवारों का बीमा करने में विफल रहे हैं। दशकों से कार्यालय की प्रकृति और संरचना में काफी बदलाव आया है और समस्याएं जटिल और लंबी हो गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित पक्षों ने इन तथ्यों को स्वीकार कर लिया है।

सन्दर्भ

1. भारत सरकार (2006-07), "आर्थिक सर्वेक्षण", वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. आनंदराजकुमार, पी., महिला बाल श्रम, ए पी एच प्रकाशन निगम, नई दिल्ली, 2004, पृष्ठ 62।
3. आजम, मोनीर (2004), "एजिंग, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी एंड रिफॉर्म", 'एन एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन सिचुएशन' इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम।
4. XXXIX, नंबर 33, 17 अगस्त पीपी। 3731-3740
5. देशपांडे, ललित के., अलख एन. शन्ना, अनूप के. करण और संदीप सरकार (2004), "लिबरलाइजेशन एंड लैबूर: लेबर फिक्सिबियटी इन इण्डियन एलवीफैन्यूफैक्चरिंग", नई दिल्ली, मानव विकास संस्थान, पृष्ठ 42:-43।
6. झा, प्रवीण (2004), "निरंतरता और परिवर्तन: उत्तर बिहार, भारत में कृषि श्रमिकों के परिदृश्य

www.ignited.in

पर कुछ अवलोकन", कृषि परिवर्तन की पत्रिका, वॉल्यूम। 4 अंक 4, पीपी. 509-531।

7. कृष्णन, पी.आर. (2004), "कन्वेंशन डिमांड्स प्रोटेक्शन टू बीड़ी वर्कर्स, सेफगार्ड्स टू इंडस्ट्री", पीपुल्स डेमोक्रेसी, वॉल्यूम। XXVIII, नंबर 3।
8. रानी, उमा और जीमोल उन्नी (2004), "भारत में असंगठित और संगठित विनिर्माण: रोजगार पैदा करने वाले विकास के लिए संभावित", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 9 अक्टूबर, पीपी। 4568-4580।
9. रहमान, एम. एम. (2004), बीड़ी वर्कर्स एंड बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर फंड - ए प्रोफाइल, वी. वी. गिरी, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा।
10. सरकार, सिद्धार्थ (2004), "वीमेन वर्कर्स इन बीड़ी रोलिंग", द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, Vo1. 47, नंबर 1, पीपी। 135-140।
11. पीटर बॉयल (2004), "तंबाकू और सार्वजनिक स्वास्थ्य: विज्ञान और नीति", https://books, google.co.in>books.
12. गुप्ता, एस.पी. (2003) "श्रम गहन निर्यात और श्रम की लागत", योजना, खंड 47, दिसंबर, पीपी 29-34।
13. आईएलओ (2003), "मेकिंग एंड्स मीट: बीड़ी वर्कर्स इन इंडिया टुडे ए स्टडी ऑफ फोर स्टेट्स", वर्किंग पेपर, सेक्टोरल एक्टिविटी प्रोग्राम, जिनेवा।
14. आईएलओ (2001), "सागर, मध्य प्रदेश, भारत के पायलट क्षेत्र में महिला बीड़ी श्रमिकों के लिए वैकल्पिक रोजगार और आय के अवसरों की पहचान", अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, नई दिल्ली और जिनेवा, सितंबर 2001।
15. अघी, एमबी (2001), "महिलाओं और बच्चों का शोषण - भारत का बीड़ी उद्योग"। एल ~ बिल्ली के समान, वॉल्यूम। 6 अक्टूबर, पीपी.8-1ओ।
16. आजम, मोनीर (2004), "एजिंग, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी एंड रिफॉर्म", 'एन एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन सिचुएशन' इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम। XXXIX, नंबर 33, 17 अगस्त पीपी। 3731-3740।
17. आलम, मोनीर और एस.एन. मिश्रा (1998), "स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड एम्प्लॉयमेंट इश्यूज इन इंडिया: ए केस ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर", द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम। 41, नहीं। 2, पीपी.271-315।

Corresponding Author

Chandraprabha Baijnath Nagde*

Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

www.ignited.in